राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00380/2024

रघुवीर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख मुख्य वन सरंक्षक (एचओएफएफ), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन सरंक्षक, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 28.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर उप वन संरक्षक कार्यालय, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान स्थान से उप वन सरंक्षक कार्यालय धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी को टीए/डीए देय होगा। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया जो कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को प्रभावित करता है क्योंकि वनपाल की वरिष्ठता रेंज वाइज होती है। अपीलार्थी को अपीलार्थी भारतीय सैना से सेवानिवृत है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण गृह जिले के भीतर ही किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की पदोन्नति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2022 वनपाल के पद पर उदयपुरवाटी रेंज में की गई। अपीलार्थी की पत्नी एएनएम के पद पर जिला झुंझुनू में अपनी राजकीय सेवाएं दे रही है जो कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण स्थान काफी दूरी पर है। इस प्रकार अपीलार्थी के परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी ने अपने

स्थानान्तरण के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधारों पर किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान उप वन संरक्षक कार्यालय, झुंझुनू में कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य